Then, he raised the question of price that will be charged by the Government for the smuggled gold. When the gold is given to the manufacturers of jewellary who export gold articles,, that is sold only at the international price because that price has to cover the gold as well as some of the wastages that are incurred. Therefore, as a result of that we will be giving them gold at the international price.

*304. [*Transferred to the 3rd September, 1990.*]

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के उपयोग हेतु होटल के कमरों का आवास स्थानों में बदला जाना

*305. **श्रीमती सूर्यकांता पाटील :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक ने एक पंचतारा होटल (सम्राट होटल नई दिल्ली) के 26 कमरों को अपने आवास स्थानों में बदल लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के परिवर्तन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम को इससे कितने राजस्व की हानि हो रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) 1988 में सम्राट होटल, नई दिल्ली, के एक विंग को जिसमें 26 कमरे हैं, अति विशिष्ट व्यक्ति के स्थान से निकट होने के कारण "सुरक्षा की दृष्टि से खतरे का क्षेत्र" निर्धारित किया गया था। अतः यह निर्णय लिया गया था कि ये कमरे आगंतुकों को किराए पर न दिए जाएं। इन कमरों का, जिन्हें वाणिज्यिक रूप से किराए पर नहीं दिया जा सकता था, वैकल्पिक व्यवहार्य उपयोग करने के लिए 1989-90 में इनमें से 22 कमरों को तीन रिहायशी एपार्टमेंट में तबदील कर दिया गया था। शेष चार कमरे इस समय खाली पड़े हैं। इन रिहायशी एपार्टमेंटस को भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मण्डल का और सरकार का अनुमोदन ले कर अध्यक्ष-एवं-प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल्स) और प्रधान प्रबंधक, सम्राट होटल को दिया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत पर्यटन विकास निगम में उपाध्यक्ष (वाइस चेयरमैन) का कोई पद नहीं है।

(ग) इस परिवर्तन पर हुए खर्च का अलग से कोई ब्यौरा नहीं रखा गया है। तथापि, 1989-90 में सम्राट होटल में परिवर्धन/फेर-बदल/सुधार करने के लिए खर्च किए गए कुल 109.50 लाख रुपये में से लगभग 50 लाख रुपये होटल के 101 कमरों के नवीकरण) (जिनमें तीन रिहायशी एपार्टमेंटस में परिवर्तित 22 कमरे शामिल हैं) पर खर्च किए गए हैं।

(घ) चूंकि ऊपर (क) और (ख) में बताए गए कारणों से ये कमरे आगंतुकों को किराए पर नहीं दिए जा सके, इसलिए इन कमरों को एपार्टमेंट में बदलने की वजह से राजस्व की हानि होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि गत पांच वर्षों के दौरान सम्राट होटल (जिसमें 268 कमरे हैं) में औसत अधिभोग 80% से कम रहा है, अतः इस वजह से सामान्यतः राजस्व की हानि नहीं हुई है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो बातें मंत्री महोदय ने कही हैं वह भ्रामक

ता है ही लेकिन असत्य पर आधारित भी है। मेरी आपको सूचना है जो मैंने खुद होटल सम्राट से जा कर राष्ट्र हित को ध्यान में रख कर एकत्रित की है। सरकार एक तरफ तो मानती है कि 22 कमरे हमने दे रखे हैं जबकि सम्राट होटल का पूरा एक विंग 26 कमरों का है जो सिर्फ तीन अधिकारियों के निवास स्थान के लिए कनवर्ट किये गये हैं। जो वर्तमान सी.एम.डी. हैं उनके नाम से 14 कमरे हैं। 10 कमरे तो वह खुद यूज़ करते हैं और अन्य चार कमरे उनके मेहमानों के लिए आरक्षित हैं। उनके पास वाइस चेयरमैन का पद नहीं है, शब्दों का हेर-फेर है वाइस चेयरमैन न हो कर कोई और है लेकिन श्रीमन मिस्टर कचरू के नाम 7 कमरे हैं। हाइली आब्जेक्शनेबल बात जो मैं कहने जा रही हूं जिसके ऊपर मेरा आब्जेक्शन है मिस्टर कचरू का खुद का निवास स्थान सी-41, पोम्पोस इन्क्लेव, नई दिल्ली में, है जिसे उन्होंने आई.टी.डी.सी. के एक अन्य अधिकारी को किराये पर दे रखा है। क्या मंत्री जी यह जानते हैं? इसी प्रकार होटल सम्राट के महा-प्रबन्धक श्री समेरवाल को पांच कमरे दिये गये हैं जिनका नम्बर 301, 303, 305, 307 और 309 है। इन 26 कमरों के 36,400 रुपये के प्रतिदिन के किराये के इलावा इन तीन अधिकारियों के होटल के खान-पान, भोजन और नौकर आदि के उपयोग से आई.टी.डी.सी. को प्रतिवर्ष करीब दो करोड़ रुपये का नुक्सान हो रहा है। क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं। मेरे प्रश्न का पार्ट (बी) यह है कि यह पूरी विंग जिसमें 26 कमरे हैं इस विंग के करीब कौन से अति विशिष्ट व्यक्तियों का आवास है जिसके आधार पर इस विंग को आपने खतरे का क्षेत्र निधारित किया है?

श्री सत्यपाल मलिक: श्रीमन, जो माननीय सदस्या ने कहा अगर ऐसे ही मान लिया जाए तो लगता है कि वाकई बहुत गलत काम हो रहा है लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। सच यह है कि 1988 में यह करीब 26 कमरे प्रधानमंत्री निवास के नजदीक होने के कारण गृह मंत्रालय सिक्युरिटी रिस्क घोषित जोन कर दिया था और यह कहा था कि इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस बात के लिए सिक्युरिटी के लोग राजी थे कि अगर होटल के अधिकारी इनका इस्तेमाल करें तो इनकी जिम्मेदारी बनती है इस पर हम को एतराज़ नहीं है। श्रीमन, नियम यह है कि होटल के जो जी.एम. होते हैं और जो सीनियर वाइस प्रेजीडेंट होते हैं यह करीब करीब होटलों में ही रहते है, प्राइवेट होटलों में भी होटल में रहते हैं। यह भी जानकारी गलत है कि मिस्टर कचरू के पास कोई दिल्ली में अपना मकान है। तो यह जो 26 कमरे थे उन में से 22 कमरों को तीन लोगों के निवास स्थान के लिए जब रेनोवेशन हो रहा था तो बदला गया था। जो अब उनका स्वरूप है उनमें एक में 4 बेडरूम, एक में तीन बेड रूम और एक में दो बेड रूम हैं। यह इस वक्त स्थिति है। श्रीमन, पूरे सम्राट होटल में पिछले चार साल में आकूपेंसी रेट एक कम अस्सी फीसदी बैठता है।

श्री सभापति: बहुत खराब चल रहा है। दूसरे होटलों में तो 130-140 प्रतिशत होता है।

श्री सत्यपाल मलिक: वह एक अलग बहस है। तो उस लिहाज से 50 से भी ज्यादा कमरे तो हर वक्त खाली रहते ही हैं। उस लिहाज से कोई बड़े भारी रेवेन्यू लास की यह चीज नहीं थी। इसलिए उस वक्त इजाजत दे दी गई। हमारी परम्परा है कि सभी होटलों में, प्राइवेट होटलों में भी **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, he is quoting the instance of private hotels in support of a public sector hotel. This is very unfortunate. *(Interruptions).*

श्री अजीत जोगी : खाली है तो एम०पी० को दे दीजिये। (**व्यवधान**)

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: He is speaking like a Samrat.

श्री सत्यपाल मलिक : बात यह है कि जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं वह तो हर हालत में हो जाएगी लेकिन वह जगह तो खाली रहनी थी। इसलिए खाली पड़ी हुई जगह, गैर इस्तेमालशुदा जिसका कोई इस्तेमाल नहीं था उस चीज़ को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए नुक्सान का कोई सवाल नहीं उठता है। नुक्सान का सवाल तो तब उठता जब हम कोई आल्टरनेटिव इस्तेमाल करते होते।

श्री सभापति : आपको यह यकीन है कि वे भरते नहीं हैं। अपने यहां ट्रिज्म बढ़ा रहे हैं। पहले ही हार मान बैठेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी।

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): Sir, as far as the hotel is concerned, these rooms, for many years now, have not been used because they overlook the residences of certain VVIPs and from the security angle, it was made amply clear that these rooms would not be occupied by any guests. It is not a question of these rooms being occupied and revenue earned. It does not arise because this was in the recommendation of the security personel and that was being followed.

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : सभापति महोदय, खुशी है कि राजस्व की कोई हानि नहीं हो रही है और खुशी इस बात की भी है कि दो करोड़ रुपये की इतनी छोटी सी रकम तीन अधिकारियों के लिए सरकार खर्च कर रही है। इसकी आप चिंता करें। मेरा सेकेण्ड सप्लीमेंट्री बड़ा स्पेसिफिक है। पब्लिक सेक्टर अण्डरटेकिंग कमेटी द्वारा अपनी 61वीं रिपोर्ट में आई०टी०डी०सी० के होटलों में आवास उपलब्ध कराने की नीति की कड़ी आलोचना किये जाने पर देश भर में आई०टी०डी०सी० के अधिकारियों को होटलों से बाहर क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? आई०टी०डी०सी० के नियमों के अनुसार 98 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाता है लेकिन कुछ चुने हुए लोग इसका लाभ न उठाकर होटलों में ही अपना आवास बनाकर रखते हैं। इन तमाम बातों को देखकर क्या सरकार इन होटलों में अधिकारियों के बजाये यात्रियों को पर्याप्त सुविधाओं के साथ स्थान उपलब्ध कराएगी तथा इस पूरे मामले की--जिसको ये कोई मामला ही नहीं मान रहे हैं लेकिन हम समझते हैं कि यह बहुत बड़े घोटाले का मामला है--जांच के लिए कोई कमेटी बैठाएंगे?

श्री सत्यपाल मलिक : महोदय, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं यह सिक्योरिटी ऐतराज की वजह से है.. (**व्यवधानण**) चुकि सिक्योरिटी के ऐतराज की वजह से उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : मेरा एक कान इधर लगा है और एक कान उधर लगा है।

SHRI A. G. KULKARNI: He is not a security risk though he has a beard.

MR. CHAIRMAN: Are you suggesting that he should be put in those quarters in Hotel Samrat?

SHRI DIPEN GHOSH: He is very much a tranquillity risk in the House.

MR. CHAIRMAN: That is why, if you put him in Hotel Samrat, then he will behave like a 'samrat'.

SHRI VISHVJIT P. SINGH: Mr. Kulkarni, it is not intended for... (*Interruptions*).

श्री सभापति : जा रहे है।

SHRI YASHWANT SINHA: If you do not stop him, he will start presiding. (*Interruptions*).

श्री सत्यपाल मलिक: मैं जवाब दे रहा था लेकिन चूंकि आपका ध्यान दूसरी तरफ था इसलिए मैं ब गया था।

श्री सभापति: मेरा ध्यान दो तरफ था। मैंने कहा था कि मेरे दो कान हैं।

श्री सत्यपाल मलिक: श्रीमन, बुनियादी बात यह है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से यह बिना इस्तेमाल की जगह हो गयी थी। नयी सरकार बनने के बाद हमने दोबारा पुलिस से इस सिलसिले में बात की और उन्होंने हमको मश्विरा दिया कि आप स्टेटस को मेन्टेन कीजिए और अभी हाल में हमने दोबारा गृह मंत्रालय को कहा कि हम इन जगहों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय की राय हमने मानी है। कहीं ऐसा नहीं है कि अगर इनका कोई और इस्तेमाल हो सकता होता तो भी हम इनका ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह शंका आप अपने दिमाग से निकाल दें।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: बात तो है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी ने जो आब्जरवेशन उठाये थे, जो सवाल किये थ उसके लिए सरकार ने अभी कदम तो उठाये लेकिन इन अधिकारियों ने जो किया नियमों में चीज है, होटलों में रहने की बात की है जिसकी वजह से दो करोड़ का नुक्सान हुआ है, जिनके कन्वर्जन में 50 लाख तो आप मान्य कर चुके हैं कि 50 लाख रुपये हमने खर्च कर दिये उनको रहने के लायक बनाने के लिए, उन्होंने प्राइवेट फ्लटस को तरह कन्वर्ट किया है, तो यह खर्च कौन उठायेगा, यह जो नुक्सान हुआ है इस खर्च को भरपाई कौन करेगा यह मैं राष्ट्रीय हित की बात कर रही हूं कोई भी व्यक्तिगत बात इसमें शामिल नहीं है।

श्री सत्यपाल मलिक: 1989-90 में तमाम होटलों के रिनोवेशन का काम शुरू हुआ था जिसमें सम्राट होटल पर 199 लाख 50 हजार रुपये का खर्च हुआ और जिसमें तमाम कमरों के रिनोवेशन पर 50 लाख रुपये लग। इन तीनों अपार्टमेंटस के रिनोवेशन पर 13 लाख 70 हजार रुपये खर्च हुए।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: सभापति जी, मेरा जो स्पेसिफिक सवाल है, वह यह था...

श्री सभापति: 25 लाख नहीं, 13 लाख खर्च हुआ है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील: ठीक है, सर। लेकिन उनके भोजन पर, उनकी और सारी सुविधाओं पर जो खर्चा होता है, क्योंकि चयरमेन और वाइस-चयरमेन जब वहां रहता है, तो जाहिर है कि वह अपने घर में तो खाना नहीं बनायेगा, होटल से ही खाना आता है। हर चीज वहां से मुहैया होती है।

श्री सभापति: इससे यह सवाल तो नहीं उठता है।

श्रीमती सूयकांता पाटील: यह तो मानने की चीज है। आप चाहें, तो आंसर दिलाइये या न दिलाइये, लेकिन यह खर्च हुआ है। इसको सरकार मानती है।

उसको वाइफकेरट करने में यह होशियारी बता रहे हैं, लेकिन यह सही चाल नहीं है। सही माने में पचास लाख रुपया इन तीन फ्लैटस पर ही खर्च हुआ है।

श्री सत्यपाल मलिक: मैं यह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पचास लाख का खर्च कुल कमरों पर हुआ है भोजन वगैरह का खर्चा वह खुद देते हैं, सरकार नहीं देती है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, yesterday the employees met me. Let me tell you frankly. The leaders of the employees' union met me and gave

me a different story. It is unfortunate that value-based politics is leading to dilution of the decision of the Public Undertakings Committee. Value-based politics is leading to dilution. Sir, the point is that the Public Undertakings Committee has strongly recommended that these rooms should be vacated. I would like to know why the decision of the Public Undertakings Committee was sought to be nullified by the Ministry on the advice of the officials who were behaving as the Samrat in the Darbar of a Moghul Empire; absolutely. This is a colossal wastage of funds. If it is a security hazard, why have the rooms been allowed to be used by them? Government do not have control on the entry of persons into the private residences of these three officials. Since Government cannot control the entry of the people, how can the use of these rooms be allowed even on security grounds? That is part (b) of my question. Part (c) is this is creating extremely bad precedents to the employees. You cannot meet their demands for lack of funds. You are running in losses. In a situation like this, you are allowing these luxurious rooms to be used by three leading personnel of the management. It is against all canons of propriety. Please answer these questions categorically. It is dilution of value-based politics.

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: It is not fair; it is not value-based politics. It is Bofors-based politics. They came by Bofors and will go by Bofors.

श्री सत्यपाल मलिक : यह विचित्र बात है, श्रीमन, कि होटल--पहले तो यह सरकार का काम नहीं है होटल चलाना, लेकिन अगर होटल्स हैं... **(व्यवधान)** हमारा जिन होटलों के साथ कम्पीटीशन है। ...**(व्यवधान)**

श्रीमन पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की कोई भी सिफारिश हो उनको हम गंभीरता से लेते हैं। मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि उनकी सिफारिशों पर हम लोग बहुत दूर तक अमल करेंगे। वह हमारी जिम्मेदारी है लेकिन जो सवाल इस वक्त हमारे सामने है सम्राट होटल का--वह एक बिलकुल बेकार जगह जो हर लिहाज से हमारी थी, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी हाल में ही, श्रीमन्, फिर हमने होम मिनिस्ट्री को लिखा है कि आप अगर हमें इसका कोई इस्तेमाल करने के लिए इजाजत दें, तो हम इनको खाली करने के लिए तैयार हैं, दूसरे इस्तेमाल के लिए।

हम अगर न कहते हों होम मिनिस्ट्री को इसके लिए, और जहां तक... **(व्यवधान)**

श्री सभापति : क्या यह कुछ मंत्रियों को नहीं दे सकते हो, जो बाहर बठ हुए हैं?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is misuse. Sir, he has to answer why the entry of the visitors into the private residences of these officials is under the control of Home Ministry Security Zone.

श्री सत्यपाल मलिक : सर जो होम मिनिस्ट्री ने कहा है--होम मिनिस्ट्री अगर उन अफसरों के रहने पर राजी है...

श्री सभापति : आपको मिनिस्ट्री के पास, इनकी बात जो हैं, उसको भी पहुंचा दिया जाए।

श्री सत्यपाल मलिक : जी, सर।

श्री सभापति : इन्होंने कहा कि वहां पर एंट्री सभी तरह के लोगों की होती है। उसके बाद भी होम मिनिस्ट्री की क्या क्या राय है कि उनको वहां रहने दिया जाए?

श्री सत्यपाल मलिक : हम होम मिनिस्ट्री की राय से ही... **(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: His question is very relevant. He says, you bring it to the notice of the Ministry that if

there are private people living there, how the entry is made, what type of people come there. In spite of that, if the Ministry says 'yes', it is good; you are on safe ground.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir,...

MR. CHAIRMAN: I have put your question. He has understood it.

SHRI DIPEN GHOSH: If it is a question of security hazard, it cannot be let out for private occupancy, whether it is a hotel board or whoever it is. How can it be, from that point of view, allowed to be used by certain officials? That means that private visitors can also visit there.

श्री सत्यपाल मलिक : होम मिनिस्ट्री ने इस बात की इजाजत दी है कि आप जिम्मेवार अफसर हैं आप रह सकते हैं।

श्री सभापति : विजिटर्स की बात कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल मलिक : यह जिम्मेवारी उन अफसरों की है। होम मिनिस्ट्री ने इसमें कोई एतराज किसी लैवल पर कभी भी नहीं किया। जब पहले प्रधान मंत्री वहां रहते थे और जब सेक्योरिटी का रिस्क बहुत ज्यादा था तब भी एतराज नहीं किया।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: What is the Minister saying?

MR. CHAIRMAN: The Minister says that the Ministry of Tourism is depending on the Home Ministry in this matters because security is under the Home Ministry.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Home Ministry didn't decide that it could be used by visitors.

SHRI DIPEN GHOSH: The question is whether those rooms are meant to be let out for people who are...

SHRI ARUN KUMAR NEHRU: Those rooms are not meant to be let out.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Chairman...

MR. CHAIRMAN: You write to me if you want to ask anything more. Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Development of Beach Tourism in Andhra Pradesh and Tamil Nadu

*306. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Central Government propose to develop beach tourism in Andhra Pradesh and Tamil Nadu in order to boost tourist traffic;

(b) whether any plan has been worked out in this regard and if so, what are the details thereof; and

(c) what concessions are proposed to be made available to the private sector for setting up hotels at these tourist centres?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SATYA PAL MALIK): (a) and (b) Ministry of Tourism in consultation with State Governments of Andhra Pradesh and Tamil Nadu have sanctioned a number of projects for development of beach resorts in the two States.

In Andhra Pradesh, Ministry has sanctioned 12 cottages for construction at Rishikonda and have provided financial assistance for purchase of water sports equipment.

In Tamil Nadu the following projects were sanctioned by the Ministry:

(a) Kanyakumari : 8 beach cottage alongwith tourists amenities at Bathing Ghats and a cafeteria; Floodlighting of Vivekanada Rock